विदेश में बसने वालों की संख्या बढ़ी

पिछले साल सितंबर में आई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि देश में जितने रईस हैं, उनमें से दो फीसदी यानी 7,000 लोग 2019 में विदेश जा बसे। इस साल के अंत तक यह संख्या और बढ़ेगी और इसमें मध्यवर्गीय लोगों का भी अच्छा-खासा हिस्सा होगा।

नीति शर्मा।।

कोरोना महामारी की दूसरी लहर में कई ऐसे लोगों ने भी अपने करीबियों को गंवाया है, जिनके पास इलाज के लिए पैसे की कमी नहीं थी। कइयों को जब अपने परिजनों या करीबियों के लिए अस्पताल में बेड की जरूरत थी, तब उन्हें बेड नहीं मिला। ऑक्सिजन सिलिंडर, रेमडेसेवियर या अन्य दवाओं को लेकर भी उन्हें उतनी ही परेशानी उठानी पड़ी। अप्रैल और मई में इन वजहों से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। इससे लोग आहत हैं और उनमें से कई अब देश छोड़ रहे हैं या उसकी योजना बना रहे हैं। वीजा और इमिग्रेशन सर्विस देने वाली कंपनियां के पास पिछले दो महीनों में विदेश में बसने को लेकर पूछताछ करने वालों की संख्या में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, कंपनियों को लगता है कि दूसरी लहर में बीमार हुए और लोग ठीक होंगे तो विदेश में बसने वालों की संख्या और बढ़ सकती है।

ऐसा नहीं है कि सामान्य वक्त में भारतीय विदेश में बसना नहीं चाहते। कोरोना महामारी के दस्तक देने से पहले भी कुछ हजार लोग हर साल देश छोड़कर जा रहे थे। उस वक्त वीजा और इमिग्रेशन सर्विस कंपनियों के पास 90 फीसदी ऐसे लोग आते थे, जो बिजनेस बढ़ाने, आसान टैक्स नीतियों और कारोबार में आसानी की वजह से दूसरे देशों में बसना चाहते थे। ये सब अमीर तबके के लोग होते थे। इस बार का मामला अलग है। अब मध्यवर्गीय लोग भी विदेश जाकर बसना चाहते हैं। उनकी प्रायॉरिटी तय है। वे ऐसे देशों में बसना चाहते हैं, जहां नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। खासतौर पर स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में।

देश में ऐसे माता-पिता की भी बड़ी संख्या है, जिनके बच्चे विदेश में नौकरी कर रहे हैं। महामारी की दूसरी लहर में इनमें से कइयों के पैरंट्स संक्रमित हुए। उनके इलाज में परेशानी हुई। इसलिए अब ये बच्चे अपने माता-पिता को अपने पास बुलाने को बेचौन हैं। पिछले साल सितंबर में आई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि देश में जितने रईस हैं, उनमें से दो फीसदी यानी 7,000 लोग 2019 में विदेश जा बसे। इस साल के अंत तक यह संख्या और बढ़ेगी और इसमें मध्यवर्गीय लोगों का भी अच्छा-खासा हिस्सा होगा।

सरकार को इस मामले की गंभीरता को समझना होगा। उसे इस 'ब्रेन ड्रेन' को रोकना होगा। समझना होगा कि यह वर्ग न सिर्फ टैक्स के रूप में अच्छा-खासा योगदान देता है बल्कि देश की आर्थिक तरक्की में भी इन कुशल पेशेवरों की बड़ी भूमिका है। आज यह वर्ग देश में अपर्याप्त हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर से नाराज है। सरकार को इसमें निवेश बढ़ाना चाहिए, जिसकी सलाह यूं भी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स लंबे समय से देते आए हैं। इससे न सिर्फ अगली मेडिकल इमरजेंसी से निपटने में मदद मिलेगी बल्कि देश से ब्रेन ड्रेन भी रुकेगा।अब मध्यवर्गीय लोग भी विदेश जाकर बसना चाहते हैं। उनकी प्रायॉरिटी तय है। वे ऐसे देशों में बसना चाहते हैं, जहां नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। खासतौर पर स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में।

कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा। ये ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर एक ऐसा मनुष्य है जिसे केवल अपनी पूजा करवानी है और ऐसा ना करने पर वह आपको दंड दे सकता है। ये सब भय का माहौल परमेश्वर के लिए इसलिए बनाया गया ताकि उनका व्यवसाय चलता रहे। आज के समय में कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड की परिभाषा और अंतर को समझाने का कष्ट कोई नहीं उठाता। हमने शायद ही किसी पुरोहित को ये कहते सुना होगा कि३

"स्वार्थ का त्याग करो"
"कर्मों को सुधारो"
"भौतिकता का त्याग करो"
"इच्छओं का शमन करो"
"ब्रह्म के मार्ग पर चलो"। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ऐसा कहने वाले को सबसे पहले अपनी इच्छाओं और स्वार्थ का त्याग करना होता है। पुरोहितों ने तो कर्मकांड में भय का मिश्रण कर उसे और ज्यादा धारदार बनाया।

संपादकीय

आजमाया हुआ नुस्खा

गुजरात में नरेंद्र मोदी की शैली थी कि वह विधानसभा चुनाव में कई विधायकों के टिकट काट देते थे। सरकार में नियमित अंतराल पर बड़ा बदलाव करते थे। इससे वह लोकल एमएलए के खिलाफ या उनके सरकार के खिलफ उपजे एंटी इनकंबेंसी को पूरी तरह काउंटर कर देते थे। इस हिसाब से 2024 के मद्देनजर बीजेपी के सासंदों को अपनी सीट की चिंता अभी से करनी चाहिए। उनका एक और आजमाया हुआ नुस्खा रहा है सरकार में पूर्व ब्यूरोक्रेटस को जगह देना। लगभग 13 वर्षों के दौरान बतौर सीएम नरेंद्र मोदी गुजरात में अपने विकास का अजेंडा पूरा करने के लिए ब्यूरोक्रेसी पर ही निर्भर रहे हैं। चाहे वायब्रेंट गुजरात हो या रेड टेप कल्चर को रेड कारपेट वेलकम में बदलने की उनकी मुहिम, यह तथ्य स्थापित होता रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स उनके बेहद करीब होकर काम करते हैं। वही आजमाया हुआ नुस्खा मोदी ने अपने पहले टर्म में दिल्ली में जारी रखा और दूसरे टर्म में भी उस पर चलते रहने के संकेत दे दिए हैं। पीएम मोदी ने पहली बार सांसद बने 50 वर्षीय अश्विनी वैष्णव को बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया। टीम में पहले से ही हरदीप पुरी, जयशंकर और आर के सिंह बेहद अहम भूमिका में हैं जो पूर्व ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं। इसी तरह हरियाणा के पूर्व ब्यूरोक्रेट सुनीता दुग्गल को भी सरकार में जगह दी गई। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो यह सब एक शुरुआत भर है। अगर सरकार-बीजेपी को अपन दबदबा फिर से पाना है तो उसे अभी कई कोर्स करने पड़ सकते हैं।

वक्त पर फैसला लेने में विश्वास करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी ने 43 नए मंत्रियों को अपनी टीम में शामिल कर एक साथ इन तमाम मोर्चों को साधने की कोशिश की।

मंत्रियों के कामकाज पर थे सवाल

नरेंद्र नाथ।।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम में अब तक का सबसे बड़ा फेरदबल किया। उनके दूसरे टर्म के दो साल से ज्यादा गुजर चुके हैं। 2014 से अब तक देश की राजनीति में एकतरफा प्रभुत्व जमाए चल रही बीजेपी की अगुआई वाली केंद्र सरकार को पिछले कुछ समय से कई मोर्चे पर जूझना पड़ रहा है। बीजेपी और सरकार को पहली बार अहसास हुआ कि अब कई स्तरों पर ऐसे सवाल उठ रहे हैं, जिनके जवाब दिए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। सरकार के सात साल पूरे होने पर आए तमाम ओपीनियन पोल में यह बात सामने आई कि सरकार की लोकप्रियता भले बनी हुई है लेकिन लोगों में कई मुद्दों पर बेचेनी बढ़ी है और अगर उसे कम करने की कोशिश अभी नहीं की गई तो आगे की राह कठिन हो सकती है। कहा गया कि कमजोर विपक्ष के कारण सरकार कई मसलों पर आम लोगों के आक्रोश से बच गई लेकिन ऐसा लंबे समय तक नहीं चल सकता। इसीलिए वक्त पर फैसला लेने में विश्वास करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी ने 43 नए मंत्रियों को अपनी टीम में शामिल कर एक साथ इन तमाम मोर्चों को साधने की कोशिश की। उनके तीर निस्संदेह नुकीले हैं, लेकिन वे निशाने पर लगे या नहीं, यह स्पष्ट होने में थोड़ा वक्त लगेगा।

केंद्र की सत्ता में सात साल पूरे होने के बाद भी ब्रांड मोदी की चमक तो बनी रही लेकिन मंत्रियों के कामकाज पर सवाल उठने लगे। ऐसी आम राय बनी कि पीएम मोदी काम करना चाहते हैं लेकिन उनके मंत्री उस गति से नहीं चल पा रहे। इसी वजह से गर्वनेंस या नीतियों को अमल में लाने में अपेक्षित कामयाबी नहीं मिल रही। सूत्रों के अनुसार बीजेपी के दर्जनों सांसदों ने शिकायत की कि मंत्री उनकी बात नहीं सुनते, क्षेत्र में काम नहीं करते और उनके कारण सरकार की किरकिरी हो रही है। उधर पीएम मोदी अपने स्तर पर भी मंत्रियों के बारे में फीडबैक लेते रहे। कोरोना ने रही-सही कसर भी पूरी कर दी। दूसरी लहर के बाद तो पीएम मोदी के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े होने लगे। कुल मिलाकर सरकार ऐसे मोड़ पर आ गई जहां से चीजें उलझी नजर आ रही थीं। दूसरे टर्म में नीतिगत फैसलों के प्रभावी तरीके से लागू नहीं होने से भी पीएमओ चिंतित था। खुद मोदी ने मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान महत्वपूर्ण प्रॉजेक्ट्स में दिख रही सुस्ती पर नाराजगी जताई। हालांकि दूसरे टर्म की शुरुआत मोदी सरकार ने आक्रामक तरीके से की थी। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के साथ-साथ नागरिकता संशोधन कानून पास किया गया। लेकिन बाद में इन्हीं मसलों को लेकर वैश्विक स्तर पर सवाल भी उठे। अभी पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया कंपनियों से सरकार का टकराव सुर्खियों में रहा। सरकार इन विवादों को दूर कर आगे बढ़ना चाहती है।

सरकार को यह भी पता है कि दो साल में अगर आर्थिक मोर्चे पर चीजें ठीक नहीं हुईं तो 2024 आम चुनाव में यह बड़ा मुद्दा बन सकता है। आर्थिक सुस्ती के बीच महंगाई, पेट्रोल-डीजल की कीमतें अभी से मुद्दा बन रही हैं। किसान आंदोलन भी सरकार की मुसीबत का कारण बना हुआ है।

अष्टयोग-5051

7		5		3		1
	33		36		27	
3		4	6	7		2
	36		30	1	26	
5		7			3	
	36	6	32		34	3
	2		4	5		

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है.खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं.गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी.सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 5050 का हल

5	7	2	4	1	6	3
2	33	1	23	6	33	6
3	7	6	1	2	4	5
4	42	4	29	4	25	4
7	6	5	4	3	2	1
6	37	7	38	7	33	2
1	2	3	4	5	6	7

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

बदलाव के नतीजे जमीन पर

मोहन। बहरहाल, सरकार से जुड़े लोगों का दावा है कि अभी बहुत वक्त है और पीएम मोदी अपनी टीम के साथ चीजों को पटरी पर लाने का माद्दा रखते हैं। उनके मुताबिक अगले कुछ दिनों में बदलाव के नतीजे जमीन पर दिखने भी लगेंगे। पूरे फेरदबल में पीएम मोदी की शैली पर 'सीएम मोदी' का भी असर दिखा है। गुजरात में बतौर सीएम मोदी एंटी इनकंबेसी को काउंटर करने के लिए समय-समय पर बड़ा बदलाव कर चौंकाते रहते थे। इनके बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली हार राजनीतिक मोर्चे पर झटका साबित हुई। मंत्रिमंडल में नए चेहरे को लाने के साथ चुनाव में पुराने लोगों का टिकट काटने की शैली वह वहां सफलतापूर्वक अपना चुके हैं। कैबिनेट फेरबदल पर गौर करें तो 2021 में नरेंद्र मोदी फिर से गुजरात मॉडल पर लौटते दिख रहे हैं जहां वह चुनाव-दर-चुनाव न सिर्फ जीतते रहे बल्कि मजबूत भी होते गए थे।